यह माना कि बंधक को भुनाया नहीं जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में संयुक्त कब्जे के लिए एक डिक्री आगे स्पष्टीकरण के साथ पारित की जानी है कि विभाजन के समय वर्तमान वादी केवल बंधक भूमि सहित पूरी भूमि में से उसके द्वारा खरीदी गई भूमि के हिस्से का हकदार होगा।

(8) दर्ज किए गए कारणों के लिए, अपील में कोई दम नहीं पाते हुए, इसे लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है। . निचली अपीलीय अदालत के निर्णय और डिक्री की पुष्टि ऊपर के अनुसार की जाती है।

एस.सी.के.

एन. सी. जैन, जे. के समक्ष

हरियाणा राज्य, - *अपीलकर्ता।*

बनाम

लखन लाल, – उत्तरदाता।

नियमित द्वितीय अपील सं. 1984 का 784।

8 मार्च, 1991।

पंजाब पुलिस नियम, 1934- *नियम* 16.2(1)- का दायरा - कदाचार *के* सबसे गंभीर कृत्य - रखरखाव की क्षमता।

यह माना गया कि कदाचार का एक भी कार्य नियम 16.2 (1) की प्रयोज्यता को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त होगा, बशर्ते कि कार्य सबसे गंभीर हो। सबसे गंभीर कार्य, निश्चित रूप से, किसी भी सख्त परिभाषा के असमर्थ है। कदाचार और गंभीर कदाचार के बीच दंड देने वाले प्राधिकारी द्वारा अंतर किया जाना चाहिए। दुराचार साधारण प्रकृति का नहीं होना चाहिए और यह हमेशा गंभीर प्रकृति का होना चाहिए। सबसे गंभीर कृत्य का मतलब यह नहीं है कि शिकायत किए गए कृत्यों की संख्या एक से अधिक होनी चाहिए। नियम 16.2 (1) में 'कृत्य' शब्द के उपयोग को कदाचार का एक सबसे गंभीर कार्य शामिल करने के लिए कहा जा सकता है। लेकिन सजा देने वाले प्राधिकारी को यह बर्खास्तगी की सजा देने से पहले इस निष्कर्ष को दर्ज करना चाहिए कि जिस कृत्य की शिकायत की गई है, वह इतनी गंभीर प्रकृति का था कि पुलिस सेवा के लिए अशुद्धि और पूर्ण अयोग्यता साबित होता।

(पैरा 7)

श्री वी. के. जैन (द्वितीय) अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, हिसार ने दिनांक 12 दिसम्बर, 1983 को श्री आर. के. कश्यप, एचसीएस, उप-न्यायाधीश, IInd क्लास, हिसार के दिनांक 24 दिसम्बर*, 1982 के आदेश को पलटते हुए (वादी द्वारा दायर की गई घोषणा के लिए मुकदमा पूरे खर्च के साथ) को पलट दिया। न्यायालय के आदेश से नियमित द्वितीय अपील।*

दावा: यह घोषणा करने के लिए वाद कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हिसार द्वारा पारित 27 अप्रैल, 1981 *का आदेश, जिसके द्वारा वादी को सेवाकर्ता से बर्खास्त कर दिया गया था, कानून की दृष्टि से असंवैधानिक है और यह वादी के लिए बाध्यकारी नहीं है कि वह राज्य की सेवा में बना रहेगा और दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य के आधार पर सभी वेतन और भत्तों का हकदार है।*

दावा अपील में: अपीलीय न्यायालय के आदेश को पलटने के लिए।

बी.एस. राणा, वकील, अपीलकर्ताओं *के लिए।*

गुरजीत सिंह बावा, एडवोकेट के साथ पी. एस. बावा, अधिवक्ता, *प्रतिवादियों के लिए ।*

निर्णय

एन. सी. जैन; जे। *(मौखिक)*

1) इस अपील में शामिल कानून का सटीक प्रश्न यह है कि पंजाब पुलिस नियम, 1934 (इसके बाद नियमों के रूप में संदर्भित) के नियम 16.2 (1) की सही व्याख्या क्या है; उपर्युक्त नियमों के नियम 16.2(1) की व्याख्या करने से पहले, हरियाणा राज्य द्वारा दायर अपील को आगे बढ़ाने के लिए मामले की जानकारी का होना आवश्यक है।

(2) वादी-प्रतिवादी ने हरियाणा राज्य के विरुद्ध घोषणा के लिए मुकदमा दायर किया, यह कहते हुए कि वह वर्ष 1962

में हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के रूप में शामिल हुआ था, और 3 फरवरी 1978 को, उनके खिलाफ एक जांच की गई और जांच के निष्कर्ष के परिणामस्वरूप, उन्हें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हिसार द्वारा दिनांक 24 जुलाई, 1978 के आदेश से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्तगी को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी गई थी। मुकदमे को प्रतिवादी द्वारा चुनौती दी गई थी। पक्षकारों के अनुरोध पर निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए गए थे -

(1)क्या एस.एस.पी. हिसार का दिनांक 24 जुलाई, 1978 का आदेश *अमान्य और असंवैधानिक* है और वादी के लिए बाध्यकारी नहीं है? ओ.पी.पी.

(2)क्या प्रतिवादी राज्य को कोई वैध नोटिस दिया गया है? ओ.पी.डी.

(3)क्या वाद वर्तमान स्वरूप में सुनवाई योग्य नहीं है? ओ.पी.डी.

(4)क्या सिविल कोर्ट के पास वर्तमान वाद पर विचार करने और विचारण करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है? ओ.पी.डी.

(5)क्या वादी को वर्तमान मुकदमा दायर करने के लिए अपने स्वयं के आचरण से रोका जाता है? ओ.पी.डी.

(6)क्या मुकदमा समय पर रोक है? ओ.पी.डी

(7) राहत।

3) ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी के पक्ष में और वादी के खिलाफ

मुद्दा नंबर 1 का फैसला किया। बाकी मुद्दों पर वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के खिलाफ फैसला सुनाया गया। मुकदमा खारिज होने के बाद, अपीलीय न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा एक अपील दायर की गई थी। अपील में, ट्रायल कोर्ट के फैसले और डिक्री को उलट दिया गया है। अपीलीय न्यायालय द्वारा यह पाया गया कि वादी की ओर से कदाचार का कार्य गंभीर कदाचार का कार्य नहीं था, अर्थात, कर्तव्य से अनुपस्थिति, और यह नियम 16.2 (1) के अनुसार, बर्खास्तगी केवल कदाचार के सबसे गंभीर कृत्य के लिए दी जा सकती है। अपीलीय न्यायालय द्वारा आगे कहा गया कि, जांच अधिकारी द्वारा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया था कि कदाचार का कार्य पुलिस सेवा के लिए वादी की अशुद्धि और पूर्ण अयोग्यता साबित करता है। सुखदेव सिंह *बनाम* पंजाब राज्य और अन्य[1], मामले में इस न्यायालय के फैसले पर निर्भरता रखी गई। हरियाणा राज्य ने अपीलीय न्यायालय के निर्णय और डिक्री के खिलाफ अपील दायर की है।

4) हरियाणा राज्य के वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि गंभीर प्रकृति के कदाचार का एक भी कार्य पर्याप्त है और यह आवश्यक नहीं है कि दंड देने वाले प्राधिकारी को *पूर्वोक्त.* नियम के नियम 16.2 को लागू करने के उद्देश्य से बर्खास्तगी के आक्षेपित आदेश में सेवा की अवधि का उल्लेख करना चाहिए। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने हरियाणा *राज्य*

[1] 1983 (2) एसएलआर 645

और अन्य बनाम गुरदेव सिंह[2] और *पूर्व कांस्टेबल जोइंदर सिंह बनाम हरियाणा राज्य*[3] *पर भरोसा किया* है। दूसरी ओर, श्री जी.एस. बावा द्वारा यह तर्क दिया गया है कि भले ही इस न्यायालय द्वारा *राज्य* के वकील की दलीलों को स्वीकार किया जाए, वादी-प्रतिवादी की बर्खास्तगी को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और इसे इस संक्षिप्त आधार पर रद्द कर दिया जाना चाहिए कि दंड देने वाले प्राधिकारी ने अपने आदेश में यह दर्ज नहीं किया कि कदाचार का कार्य पुलिस सेवा के लिए अशुद्धि और अयोग्यता साबित हुआ। उन्होंने *राम कृष्ण कांस्टेबल नंबर 141 बनाम हरियाणा राज्य और अन्य*[4], *फूल सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य*[5] और *सुखदेव सिंह* बनाम *पंजाब राज्य और अन्य*[6] पर भरोसा किया है। बार में दिए गए तर्कों की सराहना करने से पहले, नियम 16.2 (1) पर एक नज़र डालना आवश्यक है जो निम्नानुसार है: -

> "बर्खास्तगी केवल कदाचार के सबसे गंभीर कृत्यों के लिए दी जाएगी या निरंतर कदाचार के संचयी प्रभाव के रूप में जो पुलिस सेवा के लिए अशुद्धि और पूर्ण अयोग्यता साबित करती है। इस तरह के फैसले को बनाने में, अपराधी की सेवा की अवधि और पेंशन के लिए उसके दावे का ध्यान रखा जाएगा।"

(5) उपर्युक्त नियम में किसी पुलिस कांस्टेबल को केवल

[2] 1981 (3) S.L.R. 130.
[3] 1990 (2) R.S.J. 757.
[4] 1990 (1) R.S.J. 637.
[5] 1989 (61 S.L.R. 138.
[6] 1983(2) S.L.R. 645.

कदाचार के गंभीरतम कृत्यों (अर्थात् एक से अधिक कृत्यों) के लिए या पुलिस सेवा के लिए अशुद्धि और पूर्ण अयोग्यता साबित करने वाले निरंतर कदाचार के संचयी प्रभाव के रूप में बर्खास्त करने की परिकल्पना की गई है। यह भी आवश्यक है कि सबसे गंभीर कृत्यों को पुलिस सेवा के लिए अशुद्धि और पूर्ण अयोग्यता साबित करनी चाहिए। कार्रवाई करते समय प्राधिकरण को यह ध्यान में रखना चाहिए कि पुलिस अधिकारी ने कितनी सेवा की है और पेंशन के लिए उसका दावा कितना है। यह सरल अर्थ जो नियम के अवलोकन से अनुमान लगाया जा सकता है, हालांकि, इस न्यायालय की व्याख्या का विषय था। वर्ष 1983 में, *सुखदेव सिंह के* मामले (सुप्रा) में, आई. एस. तिवाना, जे. ने ड्यूटी पर नशे में पाए गए एक पुलिस अधिकारी के मामले से निपटते हुए बर्खास्तगी को इस आधार पर रद्द कर दिया कि अधिकारियों द्वारा यह कहीं भी दर्ज नहीं किया गया था कि अधिकारी कदाचार के ऐसे कृत्यों का दोषी था, जिसका संचयी प्रभाव पुलिस सेवा के लिए अशुद्धि और पूर्ण अयोग्यता साबित कर सकता है। आई. एस. तिवाना, जे. के विचार में, इस तरह के निष्कर्ष के अभाव में बर्खास्तगी की सजा का सहारा नहीं लिया जा सकता है। नियम 16.2 को प्रकृति में अनिवार्य माना गया था। वादी-प्रतिवादी के मुकदमे का फैसला करते समय अपीलीय न्यायालय द्वारा मुख्य रूप से इस प्राधिकरण पर भरोसा किया गया है। इस स्तर पर, *हरियाणा राज्य के मामले* (सुप्रा) में डिवीजन बेंच के फैसले पर एक नज़र डालना आवश्यक है, जिसमें ड्यूटी के दौरान नशे

में पुलिस अधिकारी के एक कार्य को नियम 16.2 (1) के अर्थ के भीतर सबसे गंभीर कदाचार के कार्य के रूप में माना गया था। आगे माना गया कि दंड देने वाले प्राधिकारी के लिए दोषी अधिकारी की सेवा की लंबाई, जो डिवीजन बेंच के विचार में पहले से ही रिकॉर्ड का एक हिस्सा था और अच्छी तरह से जाना जाता था, के बारे में आक्षेपित आदेश में विशेष रूप से उल्लेख करना आवश्यक नहीं था।

6) 15 सितंबर, 1989 को जे.एस. सेखों, जे., *ने* फूलसिंह मामले *(सुप्रा) में एक पुलिस अधिकारी* के मामले की जांच करते समय, *18 दिनों की अवधि के लिए ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के आधार पर सेवा से बर्खास्त कर दिए गए पुलिस अधिकारी की 12 साल की सेवा को ध्यान में रखा। जे.एस. सेखों, टी., एक और तय मामले,* 10 मार्च, 1989 के *1987 का सी.डब्ल्यू.पी. नंबर 4680* (धरम पाल पूर्व कांस्टेबल *बनाम* हरियाणा *राज्य और अन्य) पर भरोसा करने के बाद* बर्खास्तगी को रद्द करने का निर्णय लिया। *राम कृष्ण* कांस्टेबल के मामले (सुप्रा) में, ड्यूटी पर शराब के नशे में पाए गए एक पुलिस कांस्टेबल की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया गया था, क्योंकि यह माना गया था कि नियम बनाने वाले प्राधिकरण का जनादेश स्पष्ट था कि सेवा से बर्खास्तगी की सजा सामान्य प्रकृति के कदाचार में नहीं दी जानी है। *राम कृष्ण कांस्टेबल के मामले* (सुप्रा) में एम. आर. अग्निहोत्री, जे. की प्रासंगिक टिप्पणियां निम्नानुसार हैं: -

"इसमें कोई संदेह नहीं है कि दुर्व्यवहार का एक भी कृत्य किसी दी गई स्थिति में, कदाचार का सबसे गंभीर कार्य हो सकता है, लेकिन नियम बनाने वाले प्राधिकरण का जनादेश स्पष्ट है कि सेवा से बर्खास्तगी की सजा सामान्य प्रकृति के कदाचार में नहीं दी जानी चाहिए। वर्तमान मामले में, माना जाता है, -

(एक) यह याचिकाकर्ता द्वारा शराब लेने का केवल एक आवारा मामला था;

(दो) याचिकाकर्ता द्वारा यह विवादित है कि क्या वह 12 फरवरी, 1988 को रात 1.30 बजे ड्यूटी पर था, जैसा कि उनके अनुसार, वह ड्यूटी से बाहर थे;

(तीन) इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उसने शराब के नशे में उपद्रव मचाया;

(चार) याचिकाकर्ता ने नौ साल, छह महीने और ग्यारह दिन की सेवा दी थी, यानी दस साल से कम की सेवा, जो पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड II के तहत पेंशन देने के लिए अर्हक सेवा की न्यूनतम अवधि है; और

(पाँच) दण्ड देने वाले प्राधिकारी द्वारा इस आशय का कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है कि कथित कदाचार पुलिस सेवा के लिए अशुद्धि और पूर्ण अयोग्यता साबित कर रहा था और न ही अपराधी की सेवा की अवधि और पेंशन के लिए उसके दावे का सम्मान किया गया था।

उपरोक्त तथ्यात्मक और कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सेवा से बर्खास्तगी का आदेश पूरी तरह से मनमाना है और इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए।"

(6-A) अशोक भान, जे. ने हाल ही में तय *किए गए पूर्व कांस्टेबल जोगिंदर सिंह* के मामले (सुप्रा) में दो एकल पीठ के फैसलों और हरियाणा के मामले (सुप्रा) में अदालत की खंडपीठ के फैसले का हवाला *देते हुए* कहा कि उपर्युक्त नियमों के नियम 16.2 के तहत ड्यूटी के दौरान एक पुलिस अधिकारी का नशे में होना सबसे गंभीर कदाचार का कार्य था।

7) पूरे मामले का अध्ययन करने के बाद और बार में कानून का हवाला देते हुए पूरे मामले पर विचारपूर्वक विचार किया गया है, इस न्यायालय का विचार है कि कदाचार का एक भी कार्य नियम 16.2 (1) की प्रयोज्यता को आकर्षित

करने के लिए पर्याप्त होगा, बशर्ते कि कार्य सबसे गंभीर हो। सबसे गंभीर कार्य, निश्चित रूप से, किसी भी सख्त परिभाषा के लिए असमर्थ है। कदाचार और गंभीर कदाचार के बीच दंड देने वाले प्राधिकारी द्वारा अंतर किया जाना चाहिए। दुराचार साधारण प्रकृति का नहीं होना चाहिए और यह हमेशा गंभीर प्रकृति का होना चाहिए। 'गंभीरतम' शब्द के उपयोग का अर्थ केवल यह है कि यह किसी विशेष कार्य की तुलना में एक उत्कृष्ट डिग्री का होना चाहिए जिसे किसी विशेष कार्य को 'गंभीर' के रूप में वर्णित किया जा सकता है। सबसे गंभीर कृत्य का मतलब यह नहीं है कि शिकायत किए गए कृत्यों की संख्या एक से अधिक होनी चाहिए। नियम 16.2 (1) में 'कार्य' शब्द के उपयोग को एक गंभीर कृत्य के रूप में कहा जा सकता है। यह विधायी इरादे को प्रभावी बनाने के लिए आयोजित किया जाना चाहिए कि नियम 16.2 (1) में बहुवचन में उपयोग किए गए शब्द को 'एकवचन' को शामिल करने के लिए माना जाएगा। यदि दंड देने वाला प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि पुलिस अधिकारी का कोई विशेष कृत्य सबसे गंभीर कृत्यों में से एक था, तो निश्चित रूप से पुलिस अधिकारी के लिए गंभीर प्रकृति के दूसरे कृत्य के होने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि इस तरह की व्याख्या को 'कदाचार के सबसे गंभीर कृत्य' शब्दों में लिया जाए, तो अपराधी पुलिस अधिकारी यह तर्क देने के लिए एक जघन्य अपराध करेगा कि वह नियम 16.2 (1) की शरारत के दायरे में नहीं आता है। इसे ध्यान में रखते हुए, गंभीर प्रकृति का कदाचार का एक भी

कृत्य बर्खास्तगी की सजा देने के लिए नियम 16.2 (1) की सहायता से लागू करने के लिए पर्याप्त है। हालांकि, एक एकल कार्य या कृत्यों की संख्या को एक पुलिस अधिकारी के दुर्व्यवहार को पुलिस सेवा के लिए अशुद्धि और पूर्ण अयोग्यता साबित करना होगा। यह नियम 16.2 (1) का अधिदेश प्रतीत होता है। एक विशेष कार्य गंभीर या सबसे गंभीर हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि शिकायत किया गया कार्य आवश्यक रूप से पुलिस सेवा के लिए अशुद्धि और पूर्ण अयोग्यता साबित नहीं करता हो। 'अशुद्धि' शब्द का शब्दकोश अर्थ है खराब, सुधार से परे। केवल ऐसे व्यक्ति को अशुद्धि कहा जा सकता है जिसे सुधारा नहीं जा सकता है। जब 'अशुद्धि' शब्द का उपयोग विशेषण के रूप में किया जाता है, तो यह एक ऐसे व्यक्ति से संबंधित होता है जो सुधार, संशोधन में सक्षम नहीं है। किसी विशेष स्थिति में एक व्यक्ति को सबसे गंभीर कृत्यों में से एक के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, लेकिन दंडित करने वाले प्राधिकारी का अभी भी यह विचार हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति अपरिवर्तनीय नहीं है और उसे सुधारा या ठीक किया जा सकता है। सजा देने वाले प्राधिकारी का यह भी विचार हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति को ऐसा व्यक्ति नहीं कहा जा सकता जो पुलिस सेवा के लिए पूरी तरह से अयोग्य है। दूसरे शब्दों में, पुलिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत की गई सबसे गंभीर कार्रवाई अशुद्धि और पूर्ण अयोग्यता साबित नहीं हो सकती है जो नियम 16.2 (1) की प्रयोज्यता को आकर्षित करने के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। इसे ध्यान में रखते

हुए इस न्यायालय का दृढ़ मत है कि जब तक दण्ड देने वाला प्राधिकारी किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता और यह ठोस निष्कर्ष दर्ज नहीं करता कि जिस कृत्य की शिकायत की गई है वह इतनी गंभीर प्रकृति का है कि यह पुलिस सेवा के लिए अशुद्धि और पूर्ण अयोग्यता साबित होती है, मेरे विचार में बर्खास्तगी की कठोर सजा, विशेष रूप से तब नहीं सहारा लिया जा सकता है जब हरियाणा *राज्य के मामले* (सुप्रा) में इस न्यायालय की एक खंडपीठ इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि दंड देने वाले प्राधिकारी के लिए सेवा की लंबाई के बारे में आक्षेपित आदेश में विशेष रूप से उल्लेख करना आवश्यक नहीं था जो रिकॉर्ड का एक हिस्सा था और अच्छी तरह से जाना जाता था।

8) तत्काल मामले के तथ्यों के अनुसार इस मामले में इस अदालत के समक्ष यह निर्विवाद है कि सजा देने वाले प्राधिकारी ने ऐसा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया कि इस कृत्य ने वादी-प्रतिवादी की पुलिस सेवा के लिए अशुद्धि और पूर्ण अयोग्यता साबित होने की शिकायत की है। इसके मद्देनजर, इस न्यायालय के पास अपीलीय न्यायालय के निर्णय और डिक्री को बरकरार रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसके परिणामस्वरूप, हरियाणा राज्य की अपील को लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अंकिता गुप्ता
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
बिलासपुर यमुनानगर

एस.सी.के.